Government of India is about 340 calorics.

शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंयक समुदाय के छात्रों को उपलब्ध सुविधायें

1971. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं; और

(ख)इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि की गई हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : कल्याण अल्पसंख्यकों के लक्षित समूह के लिए भी आर्थिक मानदंडों के आधार पर परीक्षा पूर्व कोंचिंग की योजना कार्यान्वित कर रहा हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा नि:शुल्क वृत्तिका संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए कॉरपस निधि के रूप में 30 करोड़ रूपए के एक मुश्त अनुदान के साथ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित मौलान आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान समाज के शाक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विशेष तौर पर अन्य पिछड़े वर्गों में शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ावा देता हैं। यह प्रतिष्ठान नौकरियां तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसरण अल्पसंख्यक बहुत जिलों में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए तीन अलग योजनाओं का कार्यान्वयन करता जा रहा हैं। ये योजनाएं क्षेत्र गहन कार्यक्रम मदरसा शिक्षा तथा समुदाय पौलीटेक्रीक का आधुनिकीकरण हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के माध्यम से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए कोचिंग योजना को कार्यान्वित कर रहा हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों को नि:शुल्क वृत्तिका संबंधी कोचिंग प्रदान की जाती हैं।

(ख)मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 83.51 लाख रूपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

दुधारू पशुओं की दूध क्षमता

1977. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कूपा करेंगे कि:

(क)वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक दुधारू प्रत्येक पशु की दूध क्षमता कितनी थी;

(ख)वर्ष 1996-97 के बाद दूध क्षमता में वृद्धि करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग)क्या देश में दूध उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने हेतु दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए अनेक अनुसंधान किए गए हैं;

(घ)यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से अब तक इस संबंध में क्या-क्या अनुसंधान कार्य किए गए हैं और इनके परिणामस्वरूप पशुओं की दूध देने की क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना हैं;

(ड.)क्या इन अनुसंधनों का उपयोग ग्रामीणों के लिए सुलभ बनाने हेतु कोई व्यवस्था की गई हैं;

(च)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (छ) 1990-91 तथा 1993-94 के दौरान प्रति पशु प्रति दिन औसत दूध की पैदावार नीचे दी गई हैं। 1994-95 के नमूना सर्वेक्षण के परिणामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं:-

प्रति पशु प्रति दिन औसत दूध की पैदावार (कि0ग्रा0)		प्रतिशत वृद्धि
		1990-90
गाय	1.91	2.43 (अनन्तिम
भैंस	3.41	3.78 (अनन्तिम

1996-97 के बाद प्रति दुधारू पशु के औसत दुग्ध पैदावार की दर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास गोपशु

प्रजनन अनुसंधान तथा उत्पादन के निम्नलिखित कार्यक्रम हैं:-

1.हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश में कमशः हरियाणा तथा अंगोले जैसे संयुक्त गोपशु पशुयुध का उपयोग करके स्वदेशी नस्ल की संतति परीक्षण।

2.पी0ए0यू0, लुधियाना बी0ए0आई0एफ0, पुणे तथा के0ए0यू0, त्रिचुर में किसानों के पशुओं का उपयोग करते हुए वर्ण संकर सांडों का क्षेत्र संतति परीक्षण।

3.अन्य स्वदेशी नस्लों पर अर्थात अपने प्रजनन भू-भागों में वेचुर, पंगनूर तथा कंज्ञम के मूल्यांकन, लक्षण वर्णन तथा सुधार के कार्यक्रम प्रगति पर हैं। इसके अलावा पशुओं पर करन "स्विस" करन "फ्राइज" तथा "फ्रिसवाल" में सिरे परीक्षण का अनुसंधान कार्यक्रम क्रमशः राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल तथा गोपशु परियोजना निदेशलय में प्रगति पर हैं।

जहां तक भैंस प्रजनन अनुसंधान का प्रश्न हैं, मुर्रा तथा सुर्ती नस्लों के संतति परीक्षण पर कार्य आरम्भ किया गया हैं। इन परियोजनाओं से सांडों तथा जांच किए गए सांडों (स्वदेशी, वर्ण-संकर तथा भैंस) का वीर्य सुधार कार्यक्रमों के लिए किसानों के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

पशुपालन कार्यक्रम एवं योजना के संबंध में शिकायत

1978. **श्री नागमणि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार को छोटा नागपुर में पशुपालन कार्यक्रम एवं योजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख)यदि हां, तो यह शिकायत किस प्रकार की हैं;

(ग)क्या केन्द्रीय सरकार को संबंधित राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं;

(घ)यदि हां, तोए उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.)यदि नहीं, तोए इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को 1990 से मार्च 1992 की अवधि के दौरान आवंटित 46.50 करोड़ रूपए की राशि के कथित कुप्रबंध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार के छोटानागपुर तथा संथाल परगना के लोगों के कल्याण के लिए सुअर, भैंस, गाय/बछड़े, भेड़, बकरी, कुक्कुट तथा पशुधन चारा/आहार और औषधि आदि के मुफ्त वितरण के उद्देश्य से इन निधियों का आवंटन जिला ग्राममीण विकास एजेंसी, जनजातीय विकास एजेंसी, विशेष घटक योजना, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक संगठनों को किया गया बताया गया हैं। कथित भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सेवाओं में तैनाती, स्थानान्तरण, नियुक्तियां तथा विस्तार अनियमितताओं के उदाहारणों का भी उल्लेख किया गया हैं।

चूंकि शिकायत में उठाए गए मामले बिहार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा केन्द्रीय मंत्रालय, पशुपालन विभाग का इन मुद्दों से सीधा कोई संबंध नहीं हैं, अतः इन शिकायतों को उचित जांच-पड़ताल तथा तत्काल कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को भेज दिया था।

(ग) से (ड.) सातवीं योजना से 1994-95 तक केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों के उपयोग के बारे में राज्य पशुपालन विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी हैं। रिपोर्ट में यह प्रमाणित किया गया हैं तथा बिहार के छोटानागपुर में निधियों का किसी प्रकार का कोई कुप्रबंध नहीं हुआ हैं।

Linking of Steel outlets of SAIL by Computer Network

1979. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the steel outlets, plants and offices of Steel Authority of India Limited across the country are to be linked by a computer network;

(b) if so, the details with background thereof;

(c) whether certain outlets, plants and offices have been identified for the purpose;

(d) if so, the names of each location-wise and if not, the reasons therefor;

(e) whether consumers of steel are also to be benefited with such facility; and

(f) if so, the details and if not, the reasons therefore?